

सं. ओ. वि. एफ.डी./गुडगांव/126-87/27171.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै० कैफको, दीलताबाद रोड़, गुडगांव, के श्रमिक श्री विश्व नाथ, पुत्र श्री राम लखन, मार्फत श्री महावीर त्यागी, औरगेनाईजर, इण्टक, दिल्ली रोड़, गुडगांव, तथा प्रबन्धकों के मध्य इसमें इस के बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं।

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इस के द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण, हरियाणा, फरीदाबाद, को नीचे विनिर्दिष्ट मामले जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के बीच या तो विवादग्रस्त मामला/मामले हैं अथवा विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला/मामले हैं न्यायनिर्णय एवं पंचाट 3 मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं :—

क्या श्री विश्वनाथ की सेवा समाप्ति न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं. ओ. वि. यमुना/30-87/27178.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै० (1) परिवहन आयुक्त हरियाणा चण्डीगढ़। (2) महाप्रबन्धक, हरियाणा राज्य परिवहन, यमुनानगर, के श्रमिक श्री राम सरूप, गांव अहमदपुर, डा० सलाहपुर, बाया सड़ौरा, तहसील नारायणगढ़, जिला अम्बाला, तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इस में इस के बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इस लिये, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इस के द्वारा सरकारी अधिसूचना सं-3 (44)-83-श्रम. 3, दिनांक 18 अप्रैल, 1984, द्वारा उक्त अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, अम्बाला, को विवादग्रस्त या उन से सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है :—

क्या श्री राम सरूप की सेवाओं का समाधान न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं० ओ. वि./एफ.डी०/गुडगांव/114-87/27185.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै० इण्डो निप्पन फुडज प्रा० लि०, 7, इण्डस्ट्रियल इस्टेट, पालम गुडगांव रोड़, गुडगांव, के श्रमिक श्रीमती हंस मुखी, मार्फत मर्कनटार्डल इम्पलाईज एसोसिएशन, एच-347, न्यू राजेन्द्र नगर, नई दिल्ली-110060, तथा प्रबन्धकों के मध्य इस में इस के बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इस के द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण, हरियाणा, फरीदाबाद, को नीचे, विनिर्दिष्ट मामले जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के बीच या तो विवादग्रस्त मामला/मामले हैं अथवा विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला/मामले हैं न्यायनिर्णय एवं पंचाट 3 मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं :—

क्या श्रीमती हंस मुखी की प्रबन्धकों द्वारा सेवा समाप्ति की गई या उसने चुकती हिसाब लेकर स्वयं नौकरी छोड़ी है ? इस बिन्दु पर निर्णय के फलस्वरूप वह किस राहत की हकदार है ?

सं० ओ० वि० एफ.डी०/50-87/27192.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै० पूर्वा इंजीनियर्स लि०, 12/6, मथुरा रोड़, फरीदाबाद, के श्रमिक श्री समसुल हक, मार्फत एटक आफिस, एन. आई. टी. फरीदाबाद, तथा प्रबन्धकों के मध्य इस में इस के बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इस के द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन

गठित औद्योगिक अधिकरण हरियाणा, फरीदाबाद, को नीचे विनिर्दिष्ट मामला जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है अथवा विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला है न्यायनिर्णय एवं पंचाट 3 मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं :—

क्या श्री सममूल हक की सेवा समाप्त की गई है या उसने स्वयं ही अपनी इच्छा से चूको हिनाव प्राप्त करके नौकरी छोड़ी है? इस बिन्दु पर निर्णय के फलस्वरूप वह किस राहत का हकदार है?

सं० ओ० वि० एफ.डी./148-87/27199.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राये है कि मै० प्रवीन रिनफोर्सड प्लास्टिक प्रा० लि०, प्लॉट नं० 135, डी.एल.एफ., मथुरा रोड, फरीदाबाद के श्रमिक श्री अलाउद्दीन, पुत्र श्री जैनुन शाह मार्फत हिन्दू मजदूर सभा, 29, गद्दीद चौक, फरीदाबाद तथा प्रबन्धकों के मध्य इस में इस के बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई औद्योगिक विवाद है,

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्याया निर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उप-धारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इस के द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण, हरियाणा, फरीदाबाद, को नीचे विनिर्दिष्ट मामला जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है अथवा विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला है न्यायनिर्णय एवं पंचाट 3 मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं :—

क्या श्री अलाउद्दीन की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है?

सं० ओ० वि० एफ.डी./गुड़गांव/116-87/27206.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राये है कि मै० कैमकॉन रेलवे रोड, गुड़गांव के श्रमिक श्री मदन लाल, पुत्र श्री जांजी राम, मकान नं० 678 अर्जुन नगर, गुड़गांव तथा प्रबन्धकों के मध्य इसमें इस के बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई औद्योगिक विवाद है, और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उप-धारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इस के द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण, हरियाणा, फरीदाबाद को नीचे विनिर्दिष्ट मामला जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है अथवा विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला है न्याय निर्णय एवं पंचाट 3 मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं :—

क्या श्री मदन लाल की सेवा समाप्त न्यायोचित तथा ठीक है? यदि नहीं, तो यह किस राहत का हकदार है?

सं० ओ० वि० एफ.डी./गुड़गांव/143-87/27213.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राये है कि मै० वैस्ट्रन इंडिया इण्डस्ट्रीज लि०, 55, इण्डस्ट्रीयल इस्टेट पालम, गुड़गांव रोड, गुड़गांव के श्रमिक श्री मोहिन्द्र पाल मेहता मार्फत श्री पी. के थम्पी जनरल सेक्रेटरी वी-11 आई. डी. पी. एल. टाउनशिप, गुड़गांव तथा प्रबन्धकों के मध्य इस में इस के बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई औद्योगिक विवाद है, और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उप-धारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इस के द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण, हरियाणा, फरीदाबाद को नीचे विनिर्दिष्ट मामला जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के बीच या तो

विवादग्रस्त मामला हैं अथवा विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला है न्याय निर्णय एवं पंचाट 3 मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं :—

क्या श्री मोहिन्द्र पाल मेहता की सेवाओं का समापन/छांटी न्यायोचित तथा ठीक है? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है?

सं० ओ० वि० एफ.डी./गुडगांव/137-87/27220.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राये है कि मै० वेस्ट्रन इण्डिया इण्डस्ट्रीज लि०, 55, इण्डस्ट्रीयल इस्टेट पालम, गुडगांव रोड, गुडगांव के श्रमिक श्री मतवर सिंह मार्फत श्री पी. के. यम्पी, जनरल सैक्रेटरी, बी-II आई. डी. पी. एल. टाऊनशिप, गुडगांव तथा प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उप-धारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इस के द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण, हरियाणा, फरीदाबाद को नीचे विनिर्दिष्ट मामला जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के बीच या तो विवादग्रस्त मामला हैं अथवा विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला है, न्यायनिर्णय एवं पंचाट 3 मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं :—

क्या श्री मतवर सिंह की सेवाओं का समापन/छांटी न्यायोचित तथा ठीक है? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है?

सं० ओ० वि० पानीपत/19-87/27226.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै० (1) सचिव, हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड, चंडीगढ़, (2) कार्यकारी अभियन्ता, सिविल कन्स्ट्रक्शन डिवीजन, यर्मल पावर प्रोजेक्ट एच० एस० ई० बी० आसन, पानीपत के श्रमिक श्री सत नारायण मार्फत भारतीय मजदूर संघ जी० टी० रोड, पानीपत तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिये, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उप-धारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 3(44)84-3 श्रम/दिनांक 18-4-84 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, अम्बाला को विवादग्रस्त या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है :—

क्या श्री सत नारायण, पुत्र श्री दरिया सिंह की सेवाओं का समापन/छांटी न्यायोचित तथा ठीक है? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ;

सं० ओ० वि० एफ.डी./66-87/27234.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राये है कि मै० सिकन्दर लि०, 61, न्यू इण्डस्ट्रीयल टाऊनशिप, फरीदाबाद, के श्रमिक श्री मोहन लाल मार्फत श्री के. एल. शर्मा, उप प्रधान हरियाणा इन्डक जी-15, ओल्ड प्रैस कालोनी, फरीदाबाद तथा प्रबन्धकों के, मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिए अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उप-धारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इस के द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण, हरियाणा, फरीदाबाद को नीचे विनिर्दिष्ट मामला जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है अथवा विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला है न्यायनिर्णय एवं पंचाट 3 मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं :—

क्या श्री मोहन लाल सैटर की सेवा समाप्ति न्यायोचित तथा ठीक है? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?